

एनएचआरसी ने केआइआइटी में नेपाली छात्रा आत्महत्या मामले का लिया संज्ञान

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (केआइआइटी) में मृत पाई गई नेपाली छात्रा के मुद्दे पर ओडिशा के मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा है।

आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा कि 1 मई की घटना का हमने संज्ञान लिया है, नोटिस जारी किया है और डीजीपी और मुख्य सचिव से सात दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। मालूम हो कि फरवरी महीने में भी केआइआइटी में एक नेपाली छात्रा ने आत्महत्या की थी।

इस पर कानूनगो ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुद्दे को दबाने की कोशिश की। प्रथम दृष्टया, विश्वविद्यालय प्रशासन दोषी था, इसलिए हमने यूजीसी से सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। त्रासदी के जवाब में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के कुलपति नागेश्वर राव की अध्यक्षता में चार सदस्यीय तथ्य-खोज समिति का गठन किया है, जो केआइआइटी में हाल ही में आत्महत्या की मौतों की जांच करेगी।

मुर्शिदाबाद हिंसा: पिता-पुत्र की हत्या में एक और आरोपी अरेस्ट

■ भाषा, कोलकाता

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा के दौरान पिता-पुत्र की हत्या के मामले में एसटीएफ और एसआईटी ने शनिवार को एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस मामले में

**आरोपी
इस्लाम हत्या
की वारदात
के बाद से
फरार था**

अब तक कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी नूरुल

इस्लाम को फरक्का से गिरफ्तार किया गया। इस्लाम हत्या की वारदात के बाद से फरार था। उसे शनिवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

वक्फ (संशोधन) बिल के विरोध में आठ से 12 अप्रैल तक हुई हिंसा के सिलसिले में पिता और पुत्र सहित कम से कम तीन लोगों की मौत हुई। हिंसा में 274 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।



हिंसा में 274 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मुर्शिदाबाद का दौरा कर सकती हैं ममता बनर्जी

भाषा, कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को दो दिवसीय दौरे पर हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले की यात्रा कर सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक मनीरुल इस्लाम ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह सोमवार को जिला मुख्यालय शहर बहरामपुर पहुंचेंगी। सर्किट हाउस में रात में ठहरने के बाद वह मंगलवार को सड़क मार्ग से हिंसा प्रभावित शमशरगंज और धुलियान जाएंगी। उन्होंने कहा कि वह सुत्ती के छपघाटी मैदान में एक प्रशासनिक बैठक की अध्यक्षता भी करेंगी। बनर्जी ने पहले कहा था कि वह सामान्य स्थिति बहाल होने पर मई में इलाके का दौरा करेंगी।

KIIT girl death: NHRC, UGC launch parallel probes

RAJEEV RATHAN ■ Bhubaneswar

In the wake of the second death of a Nepali student in just three months at the KIIT University, national agencies have stepped in. The University Grants Commission (UGC) announced a four-member fact-finding committee to probe serious concerns surrounding student safety and institutional accountability on Saturday. Simultaneously, the National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of the case and demanded an Action Taken Report (ATR) from the Odisha Chief Secretary and DGP by May 9.

The latest victim, Prisha

Shah(21), was found dead under mysterious circumstances in her hostel room on Thursday, triggering a storm of protests and fresh scrutiny into KIIT's handling of student welfare, especially that of international students. Her death follows that of Prakriti Lamsal, another Nepali student who allegedly died by suicide in February after enduring sustained harassment.

On Saturday, Prisha's final rites were performed at Puri Swargadwar, after her grieving family declined to take her body back to Nepal. Her autopsy was conducted at Capital Hospital in the presence of family members, a magistrate, police officials,

and forensic experts. The final postmortem report is awaited.

The bereaved family has accused the university of ignoring repeated complaints from Prisha about harassment by a fellow student. "She had sought help, but no action was taken," a relative said, demanding an independent, high-level probe into the institutional lapses.

In a formal communication, the NHRC directed the State authorities to conduct a thorough investigation, lodge an FIR under provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), and submit the FIR copy, postmortem report, and ATR by May 9. "The safety of students is our

top priority. If necessary, we will send a team to Bhubaneswar again," NHRC member Priyank Kanungo said.

The NHRC noted, "This marks the second suspicious death of a Nepali student at the same university in less than 90 days. Allegations prima facie point to grave human rights violations."

The UGC panel, led by former IGNOU Vice-Chancellor Prof Nageshwar Rao, has been asked to probe seven specific issues, including anti-ragging mechanisms, student grievance redressal, and foreign student protection. The panel will visit the campus and is expected to submit its report within ten days.



NHRC to govt: Probe KIIT death

SUBHASHISH MOHANTY

Bhubaneswar: The National Human Rights Commission (NHRC) has directed the Odisha government to conduct a thorough investigation into the death of Prisa Sah, a first-year BTech computer science student from Nepal, who was found dead in her hostel room at the Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT).

In a notice to the chief secretary and the DGP, the NHRC gave officials time till May 9 to submit an action taken report.

Prisa's post-mortem was conducted at AIIMS on Saturday. Her body will be cremated at Puri's Swargadwara.

14 सूत्री मांगों को लेकर आशा ने किया प्रदर्शन, सीएस को मांगों का ज्ञापन सौंपा



मांगों को लेकर प्रदर्शन करती आशा.

प्रतिनिधि, कटिहार

राष्ट्रीय श्रम संगठनों के आवाहन पर आगामी 20 मई को आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में आशा एवं आशा फैसिलिटेटर भी शामिल रहेगी. इसको लेकर शनिवार को बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ के बैनर तले आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी 14 सूत्री मांगों के समर्थन में सिविल सजर्न को एक ज्ञापन सौंपा. संघ की जिला मंत्री जिफछी देवी के नेतृत्व में आशा कार्यकर्ताओं ने जिला स्वास्थ्य समिति के बाहर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की. सभी

ने कहा कि हमारी मांगें हैं कि आमलोगों को स्वास्थ्य का संवैधानिक अधिकार देते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति को योजना में तब्दील कर तमाम किस्म के संविदागत कर्मी, आउटसोर्सिंग के कर्मी एवं आशा ममता, कुरियर की सेवा नियमित किया जाय, स्वास्थ्य पर जीडीपी का छह प्रतिशत खर्चा किया जाय, श्रम सम्मेलनों एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुशंसा के आलोक में आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी सेवक घोषित किया जाय, जब तक सरकारी सेवक घोषित नहीं किया जाता है तब तक न्यूनतम वैधानिक मजदूरी

26000 रूपया दिया जाय, आशा एवं आशा फैसिलिटेटरों का एक माह से लेकर पांच माह तक का बकाया प्रोत्साहन राशि का अविलंब भुगतान किया जाय, वेलेनेस सेन्टर पर कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह देय 1000 रु की राशि का भुगतान अविलंब कराया जाय आदि मांगें शामिल हैं. सुधरी कुमारी, निपात परवीन, प्रेमलता देवी, संगीता देवी, लाडली खातून, आशा कुमारी, ललिता देवी, रुक्मणी किस्कू, जयंती देवी, नूतन कुमारी, सफिया परवीन, कलावती, सुलेखा, कंचन देवी, नीतू देवी आदि उपस्थित थी.

मानवाधिकार आयोग पहुंचे कांग्रेस पदाधिकारी

आपत्तिजनक पोस्ट पर पुलिस ने प्रदेश प्रवक्ता को किया था गिरफ्तार



संवाद न्यूज एजेंसी

मथुरा। फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता व जिलाध्यक्ष पर हुई रिपोर्ट से आहत कांग्रेसियों ने शनिवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से न्याय की गुहार लगाई है। प्रदेश प्रवक्ता ने पुलिस पर आम नागरिक के अधिकारों को हनन करने का आरोप लगाया है।

**जिलाध्यक्ष बोले-पुलिस
उत्पीड़न के खिलाफ हाईकोर्ट
में भी याचिका दाखिल करेंगे**

दरअसल, कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद ने 27 अप्रैल को फेसबुक पर अलीगढ़ में दलित किशोर पर हुए अत्याचार की वीडियो पोस्ट की थी। इसके अगले दिन 28 अप्रैल को पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था।

प्रदेश प्रवक्ता को हिरासत में लेने के बाद कांग्रेसियों व सिविल लाइन पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों से नोकझोंक हो गई थी। 29 अप्रैल को पुलिस ने प्रदेश प्रवक्ता कुंवर

सिंह निषाद व जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली।

प्रदेश प्रवक्ता ने शनिवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से उक्त मामले की जांच कराने और पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने दिल्ली जाकर आयोग के अधिकारियों को पत्र सौंपा है।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश ने बताया कि पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतर कर आंदोलन करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की जाएगी।



डीएम को दिया दिव्यांग शौचालय निर्माण कराने का निर्देश

चंदौली। नीति आयोग के आदेश पर जनपद के 71 परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग शौचालयों की निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। कार्यदाई संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की उदासीनता की वजह से शौचालयों का निर्माण नहीं हो पाया। कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों में टाइल्स, चहारदीवारी शौचालय, पेयजल और बच्चों को बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था की जा रही है। वहीं नीति आयोग ने विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों की सुविधा के हिसाब से अलग शौचालयों का नियम करने का निर्देश दिया था। इसके लिए जनपद के 71 विद्यालयों का चयन किया गया था। दिव्यांग शौचालय के लिए धन राशि भी आवंटित की गई थी। लेकिन लापरवाही के कारण यह महत्वपूर्ण

आवश्यकता पूरी नहीं हो पाई है। दिव्यांग शौचालयों के निर्माण में लापरवाही की शिकायत मानवाधिकार सी डब्लू ए के चेयरमैन योगेंद्र कुमार सिंह योगी ने आयोग में की थी। आयोग ने 1 मई 2025 को मामले पर सुनवाई करते



हुए कहा कि पिछले रिपोर्ट के अनुसार 48 विद्यालयों में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग के आदेश के पश्चात और

अधिक विद्यालयों में कार्य प्रारंभ हो गया है। परन्तु नवीन स्थिति के अनुसार 73 में 45 विद्यालयों में कार्य पूर्ण आरम्भ होना है। यह बहुत धीमी प्रगति है। आयोग ने डीएम चंदौली को निर्देश देते हुए कहा कि जिलाधिकारी दिव्यांग शौचालयों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करे तथा यह सुनिश्चित करे कि यह कार्य आठ सप्ताह के भीतर पूरा हो जाएगा। तथा इस कार्य की प्रगति को वे व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेंगे। आयोग ने दिव्यांग शौचालयों की निर्माण की लापरवाही पर सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय से पूर्व कार्य पूर्ण नहीं होता है तो आयोग डीएम को आयोग के आदेशों का अनुपालन न करने के कारणों को स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश देने के लिए बाध्य होगा।

Deccan Chronicle

Over 100 Students Fall Ill After Dead Snake Found in Meal Nation

<https://www.deccanchronicle.com/nation/over-100-students-fall-ill-after-dead-snake-found-in-meal-1876663>

DC Correspondent 3 May 2025 4:42 PM

The National Human Rights Commission (NHRC) took suo-moto cognisance of the incident and launched a formal investigation.

Patna: Over 100 children took ill after a dead snake found in a mid-day meal served to them. The incident took place on April 24 at Upkramit Madhya Vidhyalaya in Mekra village in Patna.

Many children began vomiting and complained of dizziness. The ill taken students were shifted to nearby hospitals for the treatment. The National Human Rights Commission (NHRC) took suo-moto cognisance of the incident and launched a formal investigation. The commission issued a notice to the Chief Secretary and Superintendent of Police, Patna, calling for a detailed report within two weeks. The report should include the health status of the children, it stated. (Source : Deccan Chronicle)

Times of India

'Dead snake' in mid-day meal: NHRC issues notice to Bihar govt as over 100 kids fall ill; Barh SDM denies contamination

<https://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/dead-snake-in-mid-day-meal-nhrc-issues-notice-to-bihar-govt-as-over-100-kids-fall-ill-barh-sdm-denies-contamination/articleshow/120848334.cms>

Faryal Rumi / TNN / May 3, 2025, 15:53 IST

'Dead snake' in mid-day meal: NHRC issues notice to Bihar govt as over 100 kids fall ill; Barh SDM denies contamination

In Mokama, over 100 students became ill after eating a mid-day meal. The meal was allegedly contaminated by a snake. The NHRC took notice and started an inquiry. Sick children were admitted to the hospital. Locals protested the incident. The NHRC asked for a detailed report from Bihar government and Patna police.

Over 100 students in Bihar fell ill after allegedly consuming a mid-day meal contaminated by a snake carcass, prompting an inquiry by the National Human Rights Commission.

PATNA: Over 100 school students in Mokama reportedly fell ill after consuming a mid-day meal that was allegedly contaminated by a snake carcass, which was extracted from the food prior to distribution. The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of the incident and initiated an inquiry. The incident took place on April 24 at Utkramit Madhya Vidyalaya situated in Mekra village within the Mokama block of Patna district. Locals and parents reported that a snake inadvertently fell into the cooking pot in which the rice was being prepared. After removing the dead snake, the cook purportedly distributed the food to approximately 500 students.

All the sick children were taken to Mokama Trauma Center. Some children were taken by their family and relatives to Barh Sub-division Hospital. Enraged by the incident, some of the locals and parents of the schoolkids blocked the road outside the school and created a ruckus. The NHRC has issued notices to the chief secretary of the govt of Bihar and the Senior Superintendent of Police, Patna, seeking a detailed report within two weeks. They also seek a report on the health status of the children who ate the contaminated food. In an issued statement, the NHRC stated: "Reportedly, the cook served the food to children after removing a dead snake from it. According to the media report, carried on April 25, 2025, about 500 children consumed the mid-day meal. The news about the children falling ill due to the consumption of the mid-day meal led to the blocking of the road by the protesting villagers." The Commission has observed that the contents, if true, raise a serious issue of violation of the human rights of the students.

Barh SDM Shubham Kumar dismissed all the allegations. "An investigation was conducted and initially, there was nothing substantial because rumors spread about the food contamination, and people thought something happened. However, nothing was found. The medical reports of those who fell ill did not show any specific symptoms. Kids got affected due to the heat. Additionally, due to some superstitions, people took the children to a temple and prohibited them from drinking water, which caused issues. A thorough investigation has been conducted, and there is no indication of any other cause," he told this newspaper on Saturday.

Times of India

Contaminated mid-day meal: NHRC issues notices to Bihar govt, Patna SSP after 100 schoolkids fall ill

<https://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/contaminated-mid-day-meal-nhrc-issues-notices-to-bihar-govt-patna-ssp-after-100-schoolkids-fall-ill/articleshow/120854655.cms>

Faryal Rumi / May 3, 2025, 21:55 IST

Patna: Taking suo motu cognizance of over 100 students of a school falling ill after consuming contaminated mid-day meal (MDM) in Mokama, the National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the chief secretary of the state govt and the senior superintendent of police (SSP), seeking a detailed report over the issue within two weeks. The panel also sought a report on health status of the children who ate the contaminated food. However, Barh SDM Shubham Kumar dismissed all the allegations, stating that the kids fell ill due to heat. The incident took place on April 24 at Utkramit Madhya Vidyalaya at Mekra village in Mokama block of Patna district. Locals and parents alleged that a snake inadvertently fell into the cooking pot in which the rice was being prepared. After removing the dead snake, the cook allegedly distributed the food to approximately 500 students. All the sick children were taken to Mokama Trauma Center, while some children were taken by their family and relatives to Barh sub-division hospital. Enraged over the incident, some of the locals and parents of the schoolchildren blocked the road outside the school and created a ruckus. In a statement, the NHRC said, "Reportedly, the cook served the food to children after removing a dead snake from it. According to the media report, carried on April 25, about 500 children consumed the mid-day meal. The news about the children falling ill led to the blocking of the road by the protesting villagers." The commission has observed that the contents, if true, raise a serious issue of violation of the human rights of the students.

However, the Barh SDM dismissed all the allegations. "An investigation was conducted into the matter. It was just a rumour spread about the food contamination but nothing was found in the food. The medical reports of those who fell ill did not show any specific symptoms. Kids fell ill due to the heat. Moreover, due to some superstitions, people took their children to a temple and prohibited them from drinking water, which led to health complications," he told this newspaper on Saturday.

Patna: Taking suo motu cognizance of over 100 students of a school falling ill after consuming contaminated mid-day meal (MDM) in Mokama, the National Human Rights Commission (NHRC) on Saturday issued notices to the chief secretary of the state govt and the senior superintendent of police (SSP), seeking a detailed report over the issue within two weeks. The panel also sought a report on health status of the children who ate the contaminated food. However, Barh SDM Shubham Kumar dismissed all the allegations, stating that the kids fell ill due to heat. The incident took place on April 24 at Utkramit Madhya Vidyalaya at Mekra village in

Mokama block of Patna district. Locals and parents alleged that a snake inadvertently fell into the cooking pot in which the rice was being prepared. After removing the dead snake, the cook allegedly distributed the food to approximately 500 students. All the sick children were taken to Mokama Trauma Center, while some children were taken by their family and relatives to Barh sub-division hospital. Enraged over the incident, some of the locals and parents of the schoolchildren blocked the road outside the school and created a ruckus. In a statement, the NHRC said, "Reportedly, the cook served the food to children after removing a dead snake from it. According to the media report, carried on April 25, about 500 children consumed the mid-day meal. The news about the children falling ill led to the blocking of the road by the protesting villagers." The commission has observed that the contents, if true, raise a serious issue of violation of the human rights of the students. However, the Barh SDM dismissed all the allegations. "An investigation was conducted into the matter. It was just a rumour spread about the food contamination but nothing was found in the food. The medical reports of those who fell ill did not show any specific symptoms. Kids fell ill due to the heat. Moreover, due to some superstitions, people took their children to a temple and prohibited them from drinking water, which led to health complications," he told this newspaper on Saturday.

Navbharat Times

मिड डे मील में मरा हुआ सांप! NHRC ने लिया संज्ञान, बिहार सरकार और पटना SSP को लगाई फटकार, जानें

<https://navbharattimes.indiatimes.com/state/bihar/patna/nhrc-issues-notice-to-bihar-govt-and-patna-ssp-after-100-school-kids-fall-ill-contaminated-mid-day-meal-dead-snake-in-food/articleshow/120857309.cms>

Edited by आशुतोष कुमार पांडेय | नवभारतटाइम्स.कॉम 3 May 2025, 11:28 pm

Bihar News Today: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार और पटना के एसएसपी की जमकर क्लास ली है। मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी करते हुए सरकार और पटना एसएसपी से जवाब मांगा है। मिड डे मील खाने से बीमार हुए 100 बच्चों को लेकर ये नोटिस जारी की गई है। आयोग ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।

हाइलाइट्स

मानवाधिकार आयोग ने भेजा नोटिस

पटना एसएसपी को भेजा गया नोटिस

बिहार सरकार को भेजा गया नोटिस

पटना: मोकामा में दूषित मध्याह्न भोजन (MDM) खाने से एक स्कूल के 100 से अधिक छात्रों के बीमार पड़ने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पैनल ने दूषित भोजन खाने वाले बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति पर भी रिपोर्ट मांगी है। हालांकि, बाढ़ के एसडीएम शुभम कुमार ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि बच्चे गर्मी के कारण बीमार पड़े हैं। पटना जिले का मामला

यह घटना 24 अप्रैल को पटना जिले के मोकामा प्रखंड के मेकरा गांव में उत्कर्मित मध्य विद्यालय में हुई। स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने आरोप लगाया कि एक सांप अनजाने में खाना पकाने के बर्तन में गिर गया जिसमें चावल तैयार किया जा रहा था। मृत सांप को निकालने के बाद, रसोइए ने कथित तौर पर लगभग 500 छात्रों को भोजन वितरित किया। सभी बीमार बच्चों को मोकामा ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया घटना से गुस्साए कुछ स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल के बाहर सड़क जाम कर दी और हंगामा किया।

ग्रामीणों का हंगामा

एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि कथित तौर पर, रसोइए ने बच्चों को भोजन में से मरा हुआ सांप निकालकर परोसा था। 25 अप्रैल को मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार, करीब 500 बच्चों ने मध्याह्न भोजन खाया। बच्चों के बीमार होने की खबर के कारण प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी। आयोग ने पाया कि अगर यह खबर सच है, तो यह छात्रों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है।

आयोग का दावा

हालांकि, बाढ़ के एसडीएम ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की गई। यह भोजन में मिलावट के बारे में फैलाई गई एक अफवाह मात्र थी, लेकिन भोजन में कुछ भी नहीं मिला। बीमार पड़ने वालों की मेडिकल रिपोर्ट में कोई विशेष लक्षण नहीं दिखे। बच्चे गर्मी के कारण बीमार हुए। इसके अलावा, कुछ अंधविश्वास के कारण लोग अपने बच्चों को मंदिर ले गए और उन्हें पानी पीने से मना किया, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं पैदा हुईं।

Hindu

NHRC writes to Odisha DGP and Chief Secretary in matter related to KIIT Nepalese student suicide case

<https://www.thehindu.com/education/nhrc-writes-to-odisha-dgp-and-chief-secretary-in-matter-related-to-kiit-nepalese-student-suicide-case/article69533609.ece>

Published - May 03, 2025 01:02 pm IST

ANI

The National Human Rights Commission has written a letter to Odisha's Chief Secretary and Director General of Police (DGP) over the issue of a Nepalese student who was found dead at the Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) in Bhubaneswar. Earlier, NHRC member Priyank Kanoongo said that the organisation has taken cognisance of the death of a Nepalese student at KIIT. "We will take further action after the report comes, if needed, our team will go there," said Mr. Kanoongo.

Speaking about the previous incident where another girl student was found dead on the KIIT campus, Mr. Kanoongo said the university administration tried to suppress the issue. "During our investigation, it came out that the student was sexually assaulted, pornographic content was filmed, and then she was blackmailed. When the girl complained to the college administration, instead of informing the police, the university administration tried to have a compromise and suppress the issue. Prima facie, the university administration was the culprit, so we asked the UGC to take strict action, as the environment was not conducive there," he said.

In response to the tragedy, the University Grant Commission (UGC) has constituted a four-member fact-finding committee under the chairmanship of the Vice Chancellor of Indira Gandhi National Open University (IGNOU), Nageshwar Rao, to look into the recent alleged suicide deaths at KIIT. The committee will examine the circumstances surrounding these incidents, ensure compliance with student welfare and safety regulations, and suggest measures to prevent such incidents.

The committee also includes Shashikala Wanjari, Vice-Chancellor of the National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA), and HCS Rathore, Former Vice Chancellor of Central University of South Bihar, Gaya, as a member and Sunita Siwach, Joint Secretary of UGC as the coordination officer, according to a statement from UGC on Friday. Earlier in February, Prakriti Lamsal also died by suicide at the same university.

MSN

"We have sought report from DGP, Chief secretary": NHRC member Kanoongo on KIIT suicide case

Story by ANI | • 14h • 2 min read

New Delhi [India], May 3 (ANI): National Human Rights Commission member Priyank Kanoongo has said that the NHRC has taken cognisance of the death of a Nepalese student at Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) in Bhubaneswar.

"In yesterday's (May 1) incident, we have taken cognisance, issued a notice, and sought a report from the DGP and the chief secretary, which is to be submitted within 7 days. We will take further action after the report comes... If needed, our team will go there," Kanoongo told ANI.

Speaking on the previous incident where another girl student was found dead on the KIIT campus, Kanoongo said the university administration tried to suppress the issue.

"On March 27, we submitted a report - when we had this information of a Nepali girl committing suicide, our team went there and in the investigation, it came out that that student was sexually assaulted, pornographic content was filmed, and then she was blackmailed. When the girl complained to the college administration, instead of informing the police, the university administration tried to have a compromise and suppress the issue. Prima facie, the university administration was the culprit, so we asked the UGC to take strict action, as the environment was not conducive there," he said.

Meanwhile, Central Committee member of the Mool Pravah Akhil Bharat Nepali Ekta Samaja Committee, Giriraj, demanded a fair investigation into the case.

"They did not allow us to meet the parents of the deceased...We want justice, a fair investigation should be conducted, and action should be taken against those responsible," Giriraj told ANI.

Odisha Congress President Bhakta Charan Das on Friday demanded an investigation into the death of a Nepalese student at Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) in Bhubaneswar. He said that there was a need to investigate the reason behind suicide, and preventive measures must be ensured, given that it was the second case of a student dying by suicide.

"This is the second case. The reasons behind suicide should be found out. Preventive measures need to be taken. An inquiry needs to be conducted. Without investigating the reason behind suicide, it was wrong to comment on the issue. However, there is something to it. There must be conversations among students around this to prevent such incidents further," Das told ANI.

Amid chaos over the death of a student, KIIT expressed grief over the demise of a student from Nepal, who was found dead inside her hostel room. (ANI)

Organiser

Second Nepali Student Suicide at KIIT: ABVP, UGC, NHRC launch investigations, call for ensuring accountability & action

<https://organiser.org/2025/05/03/290071/bharat/second-nepali-student-suicide-at-kiit-abvp-ugc-nhrc-launch-investigations-call-for-ensuring-accountability-action/>

May 3, 2025

Bhubaneswar — A wave of concern and condemnation has swept through KIIT (Kalinga Institute of Industrial Technology) University in Bhubaneswar following the suicide of a second Nepali student in less than three months. The deceased, identified as Prisha Shah, a first-year B.Tech student from Birgunj, Nepal, was discovered hanging in her room at the university's international girls' hostel on Thursday evening. The ABVP has condemned the State Government's silence regarding this tragic incident and is demanding firm action against those responsible. The University Grants Commission (UGC) has established a fact-finding committee on Friday to investigate the suicides of Nepali female students at KIIT University. Meanwhile, the National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of the incident.

ABVP Condemns Repeated Incidents, Demands Judicial Probe

The Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad expressed deep sorrow over the suicide of yet another Nepali student, Prisha Shah, in the international hostel of KIIT (Kalinga Institute of Industrial Technology). This marks the second suicide in two months, following the tragic death of student Prakriti in February. These incidents raise serious concerns about student safety, mental health, and administrative accountability within the university. This is not merely an "accident"; it is a glaring reflection of institutional failure.

<https://twitter.com/ABVPVoice/status/1918327408220123557>

The ongoing silence and inaction of the Odisha State Government regarding such incidents is utterly condemnable. This apathy reflects not only irresponsibility but also suggests a potential effort to shield the university administration and downplay the seriousness of these events. The repeated deaths of international students are generating significant outrage and distrust, both within India and across the global student community. The ABVP firmly demands that the Odisha Government treat these incidents with the utmost seriousness and promptly suspend the university authorities responsible. Furthermore, ABVP calls for an independent and impartial judicial inquiry into all suicide cases at KIIT University to uncover the underlying causes and ensure transparency. Additionally, mandatory reforms must be implemented across all universities and colleges to prioritise student safety, mental health, and welfare with immediate effect.

ABVP's National General Secretary, Dr. Virendra Singh Solanki, stated, "ABVP stands in full solidarity with the family of the deceased student and the Nepali student community. Why is the Odisha Government still silent after the tragic deaths of two international

students? Why has the university administration failed to ensure accountability? This is not mere negligence, but a case of institutionalised criminal insensitivity. If the government fails to act swiftly and ensure accountability in such highly sensitive matters, it will erode the trust of international students in educational institutions like KIIT. ABVP demands that the Odisha Government immediately initiate a fair investigation, take the strictest action against the guilty, and ensure that all higher educational institutions prioritise the safety and mental well-being of students through concrete and systemic measures.”

UGC Establishes Fact-Finding Committee

The University Grants Commission (UGC) has established a fact-finding committee to investigate the suicide cases of Nepali girl students at KIIT University in Bhubaneswar.

UGC Updates:

UGC has constituted a Fact-Finding Committee under the Chairmanship of Prof. Nageshwar Rao, Former VC, IGNOU to look into the students' suicide cases at KIIT, Bhubaneswar and suggest measures to prevent such incidents in future. pic.twitter.com/mXnq18vVu7

— UGC INDIA (@ugc_india) May 2, 2025

The UGC has stated that the committee will recommend measures to prevent similar incidents in the future, and it is required to submit its report within ten days from the date of this announcement.

“The UGC has constituted a Fact-Finding Committee chaired by Prof. Nageshwar Rao, former Vice-Chancellor of IGNOU, to investigate the student suicide cases at KIIT, Bhubaneswar, and to suggest measures for future prevention,” said UGC Secretary Manish Joshi.

Terms of Reference (TOR) for the Committee

- 1.Examine the circumstances surrounding the student suicide incidents, including factors such as institutional policies, academic pressure, grievance redressal mechanisms, and student support structures.
- 2.Evaluate the university's mental health support system, including counselling services, crisis intervention frameworks, faculty sensitisation programmes, and peer support initiatives.
- 3.Review compliance with relevant student welfare and safety regulations, including security protocols, grievance redressal mechanisms, and anti-harassment measures.
- 4.Conduct an on-site assessment to verify the actual implementation of student safety and well-being policies, beyond mere documented compliance.

5.Engage with stakeholders, including students, faculty, administrators, and support staff, to assess institutional culture, student experiences, and challenges faced.

6.Ensure compliance with the Guidelines for the Promotion of Physical Fitness, Sports, Student Health, Welfare, Psychological and Emotional Well-Being at Higher Educational Institutions in India.

7.Submit a detailed report with findings and recommendations to the UGC aimed at strengthening student safety mechanisms and enhancing institutional accountability.

NHRC Issues Notice, Seeks Report from Odisha Authorities

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of the death of a Nepali student at the Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT), Bhubaneswar, marking the second such incident in recent months. The NHRC has issued notices to the Chief Secretary of Odisha and the Director General of Police under Section 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993, demanding an Action Taken Report (ATR) by 9 May.

NHRC member Priyank Kanoongo confirmed on the social media platform X that a female Nepali student allegedly died by suicide on the KIIT campus. The Commission expressed serious concern over the recurrence of such incidents, emphasising the need for stringent student safety protocols.

<https://twitter.com/KanoongoPriyank/status/1918162755372319090>

“Another Nepali girl student of Odisha’s KIIT University committed suicide. In a similar incident last month, the NHRC investigated and issued its recommendations, pointing to procedural lapses in ensuring student safety. However, the University approached the Hon’ble Odisha High Court, which stayed the recommendations of the Commission. We are taking cognizance of the recent incident,” Kanoongo posted on X.

The NHRC had previously conducted an inquiry into the death of another Nepali student at the same university. The investigation revealed alleged procedural lapses by the university administration in ensuring the safety and well-being of its students. The Commission had issued a set of recommendations aimed at improving institutional accountability and safeguarding student rights.

Family and Friends in Shock

The family of the Nepali girl student from KIIT, who tragically lost her life Thursday night, arrived in Bhubaneswar on Friday. They reported that their last conversation with their daughter was at 3.00 PM yesterday, during which she seemed fine.

By 8.00 PM that same evening, they received a phone call informing them of the incident and the sad news of their daughter’s demise, said a relative of the deceased.

“We had spoken with her at around 8.00 PM. She seemed normal and spoke with us for some time. Later, we heard about her death,” expressed the parents of victim Prisha Sah.

It is worth noting that a first-year B.Tech student from Nepal was found dead at the Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) in Bhubaneswar on Thursday evening. The deceased, identified as Prisha Shah, a resident of Birgunj, Nepal, was reportedly discovered hanging in her room at the university's international girls' hostel.

This incident closely follows the death of another Nepali student, 20-year-old Prakriti Lamsal, a third-year computer science student at KIIT, whose body was also found in a hostel room in February 2025. That case led to the police detaining a fellow student and sparked protests from the Nepali student community, as well as diplomatic outreach by Nepal.

Times of India

Nepalese student cremated in Puri

<https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/nepalese-student-cremated-in-puri/articleshow/120856390.cms>

Hemanta Pradhan / May 3, 2025, 22:52 IST

Bhubaneswar: Postmortem examination of the Nepalese student, who took her own life, was conducted at AIIMS Bhubaneswar on Saturday, before the body was handed over to her family members in presence of senior state govt officers. Her last rites were performed at Swargadwar in Puri. The 18-year-old Nepali girl allegedly killed herself at KIIT here on Thursday. DCP (Bhubaneswar) Jagmohan Meena said an investigation into the death is underway. "We completed the postmortem under proper videography. A team of four doctors conducted the postmortem. Family members have not registered any complaint so far," he said. He said police force have been deployed at the campus as a preventive measure. "The situation is under control," he added. Police sources said they spoke to some friends of the deceased girl to elicit information regarding the incident.

"We are investigating the case from all angles. The scientific team is collecting evidence related to the case," said additional DCP Prakash Kumar Pal. The deceased's father told the media on Saturday that he wanted justice. "We spoke to our daughter over telephone on May 1 afternoon. She was fine at that time. After a few hours, we got information about her death. We want to know how she died," he added. The uncle of the deceased said the girl could not have taken such an extreme step as she was mentally strong. The National Human Rights Commission (NHRC) has also asked for an action taken report from Odisha chief secretary and DGP regarding the May 1 death in the private university.

NHRC also issued a notice to the govt in the earlier death case. Earlier, a Nepali girl student from the same university was found dead inside her hostel room three months ago. This incident created a hue and cry in the state and country. The Nepal govt took up the matter with the Indian govt at that time.

Odisha Bytes

Last Rites Of Nepali Student Prisha Saha To Be Conducted At Puri's Swargadwar

<https://odishabytes.com/last-rites-of-nepali-student-prisha-saha-to-be-conducted-at-puris-swargadwar/#:~:text=Bhubaneswar%3A%20The%20last%20rites%20of,at%20Swargadwar%20in%20Odisha's%20Puri.>

by OB Bureau May 3, 2025 in Bhubaneswar, City, Top Headlines Reading Time: 3 mins read

Bhubaneswar: The last rites of the Nepalese student Prisha Saha, who was found dead inside her hostel room at Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) in Bhubaneswar, will be conducted at Swargadwar in Odisha's Puri.

According to sources, the parents of the deceased student have arrived in the city and the postmortem is currently underway at AIIMS here. The entire process is being videographed in accordance with the standard operating procedure.

Prisha's mortal remains will then be taken to Puri for the traditional last rites, a police officer told the media.

The body of the first-year computer science BTech student was found hanging in her room in the girls' hostel on Thursday evening. The matter is being treated as an unnatural death, according to Bhubaneswar-Cuttack Commissioner of Police Suresh Dev Datta Singh.

"Though preliminary investigation suggests there might have been a love affair angle to the incident, we are yet to arrive at any conclusion. The student's parents along with her brother have arrived in Bhubaneswar to take her body. We are yet to interrogate them," said the police officer.

The family was informed about her death at around 8 pm on May 1. Prisha's father told the media that he had spoken to her at 3 pm on that day and she sounded fine. "My granddaughter did not seem to be under any mental stress. She was a brilliant student. She had visited us about a month ago. Someone might have killed her here to take revenge," Prisha's grandfather told the media.

Meanwhile, the National Human Rights Commission (NHRC) sent a notice to the DGP and Chief Secretary demanding an Action Taken Report (ATR) in connection with the death of the student, the second from the Himalayan kingdom at the institute within three months.

This came a day after the UGC established a four-member fact-finding committee chaired by Nageshwar Rao, Vice Chancellor of Indira Gandhi National Open University, to examine the circumstances surrounding the student suicide incidents, including factors

such as institutional policies, academic pressure, grievance redressal mechanism and student support system.

Earlier, Nepal's foreign minister Arzu Rana Deuba had said that diplomatic steps have been initiated for a proper investigation into the student's death.

In a separate statement, Nepal's ambassador to India, Shankar Sharma, said that the embassy is closely coordinating with the external affairs ministry, Odisha government, the police and the university for a "thorough investigation".

The Ministry of External Affairs also stated that India takes safety of international students "very seriously" while assuring that the Government of Odisha has "extended full support to the family of the deceased and a thorough enquiry is currently being conducted by the Odisha Police."

STATEMENT FROM KIIT

The KIIT authorities are deeply saddened and distressed by the unfortunate incident of a student's suicide on campus. It is with a heavy heart that we express our deepest condolences on the tragic and untimely death of one of our students from Nepal, a young girl pursuing her studies in the 1st year B. Tech Computer Science.

Upon discovering the incident, the hostel authorities promptly informed the local police. The police arrived at the scene, and the student's body was recovered in their presence. She was immediately taken to KIMS Hospital, where she was declared brought dead. Subsequently, the body was transferred to AIIMS Bhubaneswar for further procedures. Upon receiving the news, senior police officials reached the scene and monitored all the procedures along with a scientific team and carried out a preliminary investigation immediately.

The University administration has informed the student's family immediately and is extending full cooperation to the police in their investigation. We mourn this irreparable loss and stand in solidarity with her family, friends, and the entire Nepali student community during this extremely difficult time.

May her soul rest in peace

Janta Se Rishta

NHRC ने KIIT नेपाली छात्र आत्महत्या मामले में ओडिशा के डीजीपी और मुख्य सचिव को लिखा पत्र

<https://jantaserishta.com/local/odisha/nhrc-writes-to-odisha-dgp-and-chief-secretary-in-kiit-nepali-student-suicide-case-3992156>

Gulabi Jagat3 May 2025 6:50 PM

भुवनेश्वर : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (केआईआईटी) में मृत पाई गई नेपाली छात्रा के मुद्दे पर ओडिशा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को एक पत्र लिखा है। इससे पहले, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा कि संगठन ने भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (केआईआईटी) में एक नेपाली छात्रा की मौत का संज्ञान लिया है। "कल (1 मई) की घटना में, हमने संज्ञान लिया है, एक नोटिस जारी किया है, और डीजीपी और मुख्य सचिव से एक रिपोर्ट मांगी है, जिसे 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है। रिपोर्ट आने के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे... अगर जरूरत पड़ी, तो हमारी टीम वहां जाएगी," कानूनगो ने एनआई को बताया। पिछली घटना पर बोलते हुए जहां केआईआईटी परिसर में एक और छात्रा मृत पाई गई थी, कानूनगो ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की।

उन्होंने कहा, "27 मार्च को हमने रिपोर्ट पेश की थी - जब हमें नेपाली लड़की द्वारा आत्महत्या करने की सूचना मिली, तो हमारी टीम वहां गई और जांच में पता चला कि उस छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न किया गया, अश्लील सामग्री फिल्माई गई और फिर उसे ब्लैकमेल किया गया। जब लड़की ने कॉलेज प्रशासन से शिकायत की, तो पुलिस को सूचित करने के बजाय, विश्वविद्यालय प्रशासन ने समझौता करने और मामले को दबाने की कोशिश की। प्रथम दृष्टया, विश्वविद्यालय प्रशासन दोषी था, इसलिए हमने यूजीसी से सख्त कार्रवाई करने को कहा, क्योंकि वहां का माहौल अनुकूल नहीं था।" इस त्रासदी के जवाब में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने हाल ही में केआईआईटी में कथित आत्महत्या की घटनाओं की जांच करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के कुलपति नागेश्वर राव की अध्यक्षता में चार सदस्यीय तथ्य-खोज समिति का गठन किया है। समिति इन घटनाओं से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करेगी, छात्र कल्याण और सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी और ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाएगी। यूजीसी की ओर से शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार, समिति में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एनआईपीए) की कुलपति शशिकला वंजारी और दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया के पूर्व कुलपति एचसीएस राठौर भी सदस्य हैं तथा यूजीसी की संयुक्त सचिव सुनीता सिवाच समन्वय अधिकारी हैं। इससे पहले फरवरी में इसी विश्वविद्यालय में प्रकृति लामसाल की भी आत्महत्या से मौत हो गई थी। (एनआई)

Jagran

NHRC ने केआईआईटी नेपाली छात्रा आत्महत्या मामले में ओडिशा के DGP और मुख्य सचिव को लिखा पत्र

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने केआईआईटी में नेपाली छात्रा की आत्महत्या के मामले में ओडिशा के मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा है। आयोग ने घटना का संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले NHRC ने केआईआईटी परिसर में हुई एक और छात्रा की मौत पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मामले को दबाने की कोशिश करने की बात कही थी।

<https://www.jagran.com/odisha/bhubaneshwar-nhrc-wrote-a-letter-to-odisha-dgp-and-chief-secretary-in-kiit-nepali-student-suicide-case-23930519.html>

By Sheshnath Rai Edited By: Piyush Pandey Updated: Sat, 03 May 2025 10:37 PM (IST)

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (केआईआईटी) में मृत पाई गई नेपाली छात्रा के मुद्दे पर ओडिशा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखा है।

इससे पहले, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा कि संगठन ने भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (केआईआईटी) में एक नेपाली छात्रा की मौत का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि 1 मई की घटना को हमने संज्ञान लिया है, एक नोटिस जारी किया है और डीजीपी और मुख्य सचिव से एक रिपोर्ट मांगी है, जिसे 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है। रिपोर्ट आने के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हमारी टीम वहां जाएगी।

मुद्दे को दबाने की कोशिश

पिछली घटना, जहां केआईआईटी परिसर में एक और छात्रा मृत पाई गई थी पर बोलते हुए कानूनगो ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की। 27 मार्च को, हमने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जब हमें एक नेपाली लड़की के आत्महत्या करने की यह जानकारी मिली, तो हमारी टीम वहां गई और जांच में यह सामने आया कि उस छात्रा का यौन उत्पीड़न किया गया था, अश्लील सामग्री फिल्माई गई थी और फिर उसे ब्लैकमेल किया गया था।

छात्रा ने कॉलेज प्रशासन से शिकायत की तो पुलिस को सूचना देने के बजाय विश्वविद्यालय प्रशासन ने समझौता कर मुद्दे को दबाने का प्रयास किया। प्रथम दृष्टया, विश्वविद्यालय प्रशासन दोषी था, इसलिए हमने यूजीसी से सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा, क्योंकि वहां माहौल अनुकूल नहीं था।

मौतों की जांच करेगी समिति

इस घटना के जवाब में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के कुलपति नागेश्वर राव की अध्यक्षता में चार सदस्यीय तथ्य-खोज समिति का गठन किया है, जो केआईआईटी में हाल ही में कथित आत्महत्या की मौतों की जांच करेगी। समिति इन घटनाओं के आसपास की परिस्थितियों की जांच करेगी, छात्र कल्याण और सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी और ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाएगी।

समिति में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एनआईपीए) की कुलपति शशिकला वंजारी, गया स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एचसीएस राठौर, समन्वय अधिकारी के रूप में यूजीसी की संयुक्त सचिव सुनीता सिवाच शामिल हैं। इससे पहले फरवरी में प्रकृति लम्साल ने भी इसी विश्वविद्यालय में आत्महत्या कर ली थी।

First Bihar

Bihar human rights violation: थाना लॉक-अप में युवक की पिटाई का मामला गरमाया, मानवाधिकार आयोग ने SSP मुजफ्फरपुर को भेजा नोटिस!

Bihar human rights violation: मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात थाना में युवक की लॉक-अप में बर्बर पिटाई ने मानवाधिकार आयोग को भी झकझोर दिया है। आयोग ने एसएसपी को नोटिस जारी कर 8 हफ्तों में रिपोर्ट मांगी है।

<https://firstbihar.com/crime/muzaffarpur-police-custodial-violence-bihar-human-rights-violation-687858>

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 03 May 2025 10:36:43 AM IST

Bihar human rights violation: पानापुर करियात थाना में एक युवक रौशन प्रताप सिंह को लॉक-अप में बंद कर बेरहमी से पीटे जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है।

अब बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग (BHRC) ने इसपर सख्ती दिखाते हुए मुजफ्फरपुर एसएसपी को नोटिस जारी किया है और 8 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह मामला तब सामने आया जब पीड़ित परिवार ने मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा के माध्यम से BHRC और NHRC (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) में याचिका दायर की।

जानिए क्या है मामला:

रौशन प्रताप सिंह अपने साले अमन कुमार से मिलने पानापुर करियात थाना पहुँचे थे, जहाँ अमन पहले से ही हिरासत में था। पीड़ित पक्ष के अनुसार, थानाध्यक्ष राजबल्लभ यादव ने अमन को छोड़ने के एवज में एक लाख रुपये की मांग की। जब रौशन ने इसका विरोध किया, तो पुलिस ने उसे भी हाजत में बंद कर दिया और मुँह, हाथ और पैर बांधकर बेरहमी से पीटा। पीड़ित परिवार के अनुसार, 70,000 रुपये लेने के बाद दोनों को छोड़ा गया, और रौशन की Apache बाइक जब्त कर ली गई, जिसे छोड़ने के लिए 30,000 रुपये की अतिरिक्त मांग की गई।

इलाज और कानूनी कार्रवाई:

गंभीर रूप से घायल रौशन को पहले पीएचसी कांटी और फिर एसकेएमसीएच रेफर किया गया। मामले में रौशन की मां बीना सिंह ने याचिका दाखिल करवाई। मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने कहा, "यह मानवाधिकार हनन का गंभीर मामला है। न्यायिक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उच्चस्तरीय जांच आवश्यक है।" आयोग ने अगली सुनवाई की तारीख 10 सितंबर तय की है।

Tirhut Now

मुजफ्फरपुर: पुलिस लॉक-अप में युवक की पिटाई, मानवाधिकार आयोग ने SSP को भेजा नोटिस।

<https://tirhutnow.com/muzaffarpur-youth-beaten-up-in-police-lock-up-human-rights-commission-sends-notice-to-ssp/>

Posted by: tirhutnow | May 3, 2025

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर करियात थाने में पुलिस द्वारा एक युवक की लॉक-अप में बेरहमी से पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को नोटिस जारी कर 8 सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर रिश्वतखोरी और क्रूरता के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

क्या है पूरा मामला?

मामला पानापुर करियात थाने का है, जहां पीड़ित रौशन प्रताप सिंह अपने साले अमन कुमार से मिलने थाने पहुंचे थे। अमन को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि थानाध्यक्ष राजबल्लभ यादव ने अमन को छोड़ने के बदले रौशन से 1 लाख रुपये की रिश्वत मांगी। जब रौशन ने इसका विरोध किया, तो थानाध्यक्ष ने गुस्से में आकर उन्हें भी हाजत में बंद कर दिया। आरोप है कि रौशन के हाथ, पैर और मुंह बांधकर उनकी बेरहमी से पिटाई की गई।

परिवार के अन्य सदस्यों के थाने पहुंचने पर थानाध्यक्ष ने दोनों को छोड़ने के लिए 1 लाख रुपये की मांग की। अंततः 70 हजार रुपये लेकर रौशन और अमन को रिहा किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने रौशन की अपाचे मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में ले लिया और उसे वापस करने के लिए 30 हजार रुपये की अतिरिक्त मांग की।

पीड़ित की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती

पुलिस की पिटाई से रौशन प्रताप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल कांटी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (SKMCH) रेफर कर दिया गया।

मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

रौशन की मां बीना सिंह ने मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा के माध्यम से बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं। बिहार मानवाधिकार आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए SSP मुजफ्फरपुर को नोटिस जारी किया और 8 सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। आयोग में इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर, 2025 को होगी।

मानवाधिकार अधिवक्ता की मांग: उच्चस्तरीय जांच जरूरी

मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा ने इस मामले को मानवाधिकार उल्लंघन का अति गंभीर मामला करार दिया। उन्होंने कहा, “पुलिस की इस बर्बरता और रिश्वतखोरी ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

मामले की निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए उच्चस्तरीय जांच जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि SSP मुजफ्फरपुर जल्द ही आयोग को निष्पक्ष रिपोर्ट सौंपेंगे।

पुलिस प्रशासन पर बढ़ा दबाव

यह मामला मुजफ्फरपुर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। स्थानीय लोगों और मानवाधिकार संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

Times of India

`Nat'l disgrace': TMC slams BJP-led Centre over NHRC `downgrading'

<https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/natl-disgrace-tmc-slams-bjp-led-centre-over-nhrc-downgrading/articleshow/120858842.cms>

Dwaipayan Ghosh / May 4, 2025, 01:49 IST

Kolkata: Citing reports by a section of the media that the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) had recommended downgrading India's NHRC from category A to category B, TMC on Saturday claimed this was a "price India was paying for BJP's relentless capture of autonomous institutions". It also called the development a "national disgrace". This is the first time in its history that NHRC's global status could be downgraded, after the GANHRI sub-committee on accreditation's latest recommendation.

"Now, the UN has sounded the alarm: @India_NHRC is no longer functioning independently and should be downgraded from the prestigious 'A' category to 'B' over its failure to meet international standards. Reports state the commission is acting with clear political bias and targeting individuals based on their political affiliations. Shockingly, there is no woman in the leadership body of the NHRC. This damning indictment exposes what we've known all along: BJP-led central govt has systematically hijacked and politicised independent institutions to serve its own authoritarian agenda!" TMC posted on X.

"...This is not just institutional decay, it's a national disgrace scripted by a regime that thrives on control, not constitution," TMC wrote in another post. The party has been consistently claiming that NHRC had been politicised. Following the Murshidabad violence, Trinamool had asked whether the travel bills of NHRC and NCW were approved only if they had flight tickets to Bengal.

Pune Mirror

Ragging Claims 51 Lives in 2 Years, Urgent Reform Needed

Human rights activists, law enforcement officers, law courts, governments, and educationists have joined the battle against ragging

<https://punemirror.com/columns/columnists/ragging-claims-51-lives-in-2-years-urgent-reform-needed/cid1746268032.htm>

By PuneMirror Bureau | Reported By PMB Desk | Sat, 3 May 2025 03:54 pm

By Sunilchandra Dal

Imagine the joy parents get when their child is admitted to a prestigious professional college. Celebrations follow especially when the student gets entry into a premier institution in fields like medicine or engineering. It is a moment of immense pride and happiness for the entire family. But when that same enthusiastic student returns home broken — wanting to quit studies or, tragically, in some cases, driven to end his or her life due to the unbearable torture of ragging —! the heartbreak for the family is unimaginable. This is a stark picture of the inhuman act of ragging and offers a disturbing glimpse into the minds of those who commit such acts. A total of 51 deaths were reported from 2022 to 2024. This shows how serious the problem is. It is clear that ragging is not a friendly practice, but an inhuman act indulged in by criminals. Human rights activists, law enforcement officers, law courts, governments, and educationists have joined the battle against ragging. However, it remains a significant issue, requiring urgent attention and reform. A case of ragging was reported from the city-based BJ Medical Government College, a premium institute from which doctors have made a mark across India. The authorities have taken action and as a result, three second-year students from the orthopaedic department were suspended and expelled from the hostel.

The law against ragging

Maharashtra is one of the leading states in the country in the field of education. No doubt, the incidence of ragging is there, but the government has taken steps against it. The Maharashtra Prohibition of Ragging Act, 1999 defines ragging as display of disorderly conduct, doing of any act which causes physical or psychological harm or causes fear or shame to a student in any educational institution and includes teasing, abusing, threatening or playing practical jokes or causing hurt to the student; or asking a student to do any act which the student will not willingly do. Section 4 of the law states that whoever directly or indirectly commits ragging may be punished with imprisonment for a term which may extend to two years and also be liable to a fine of up to Rs 10,000. Section 5 lays down that any student convicted of ragging shall be dismissed from the educational institution and not admitted to any other institution for five years.

Section 6 imposes on the head of the institution the duty to enquire into any complaint against ragging within seven days and if found true, suspend the accused student and forward the complaint to the police. If the head of the institution fails to act on a complaint of ragging, such person shall be deemed to have abetted the ragging and punished accordingly.

Incidence of ragging

According to the Society Against Violence in Education (SAVE), 40% of students face ragging in some form or the other and only 8.6 percent report it. SAVE also conducted an RTI query in 2016 and found that out of 13,49,437 calls received by the national anti-ragging helpline, only 770 complaints were lodged. Students fear to lodge complaints out of fear of retribution. Students staying in hostels are especially considered as soft targets. SAVE also studied the calls received at the national anti-ragging helpline. Out of 3,156 calls from 1,946 colleges across India, medical colleges account for 38.6 percent of the total complaints, 35.4 percent of serious complaints, and 45.1 percent of total ragging-related deaths. Obviously medical colleges are becoming hotspots of ragging.

Effect of ragging on students

Ragging arises due to criminal mindset, peer pressure, group dynamics, desire for group affiliation, and desire to assert control over newcomers. The victims experience psychological distress, loss of self-esteem, and behavioural changes leading to addiction or aggression and depression as a result. Both the **National Human Rights Commission** and the Supreme Court of India have observed that ragging is a violation of human rights. The NHRC regularly intervenes in serious cases and issues notices to the authorities, demanding appropriate action.

Solutions

The University Grants Commission (UGC) has taken a strict view against ragging and issued instructions to educational institutes. A website to help victims, <https://www.antiragging.in> has been set up. A national 24x7 toll-free helpline 1800-180-5522 is active to cater to queries and complaints. The website is managed by Centre for Youth (C4Y), which is the monitoring agency in association with the Union Ministry of Education and the UGC to support the National Ragging Prevention Programme. C4Y monitors the helpline, offers technological support, and creates awareness to demote ragging.

Zero tolerance for ragging

Only a determined push by all stakeholders, with a mindset of zero tolerance for ragging, can help stop the incidence of ragging. First year students fighting for their rights against ragging should ensure that no newcomers suffer in subsequent years. Student unions too should take a pledge not to indulge in ragging.

More publicity needs to be given to those who are convicted of ragging as this will act as a deterrent. It is not known how many human rights abuse cases take place due to ragging. More research in this field is needed.

Amar Ujala

Mathura News: रिपोर्ट दर्ज होने पर मानवाधिकार आयोग पहुंचे कांग्रेस पदाधिकारी

<https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/mathura/congress-officials-reached-human-rights-commission-after-the-report-was-filed-mathura-news-c-369-1-mt11009-129033-2025-05-04>

अमर उजाला ब्यूरो | Updated Sun, 04 May 2025 12:27 AM IST

मथुरा। फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता व जिलाध्यक्ष पर हुई रिपोर्ट से आहत कांग्रेसियों ने शनिवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से न्याय की गुहार लगाई है। प्रदेश प्रवक्ता ने पुलिस पर आम नागरिक के अधिकारों को हनन करने का आरोप लगाया है।

दरअसल, कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद ने 27 अप्रैल को फेसबुक पर अलीगढ़ में दलित किशोर पर हुए अत्याचार की वीडियो पोस्ट की थी। इसके अगले दिन 28 अप्रैल को पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। प्रदेश प्रवक्ता को हिरासत में लेने के बाद कांग्रेसियों व सिविल लाइन पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों से नोकझोंक हो गई थी। 29 अप्रैल को पुलिस ने प्रदेश प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद व जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली।

प्रदेश प्रवक्ता ने शनिवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से उक्त मामले की जांच कराने और पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने दिल्ली जाकर आयोग के अधिकारियों को पत्र सौंपा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश ने बताया कि पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतर कर आंदोलन करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की जाएगी।